पूर्वोत्तर : एक आर्थिक परिदृश्य

मंजुला वाधवा

पूर्वोत्तर क्षेत्र का तकरीबन 70% इलाका पहाड़ी है और इसमें लगभग 30% आबादी रहती है और शेष 30% इलाका समतल है जहां 70% आबादी निवास करती है। भौगोलिक कारणों व अविकसित परिवहन व्यवस्था की वज़ह से शेष भारत के साथ संपर्क हमेशा मुश्किल रहा है। साथ ही, असम के ब्रह्मपुत्र और बराक घाटियों में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित होने की वज़ह से न सिर्फ असम बल्कि अन्य राज्यों पर भी काफी दबाव पड़ता है

सिक्किम समेत सात अलग लेकिन आसन्न राज्यों का समूह 'पूर्वोत्तर' निश्चित रूप से अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक महत्व के कारण हमारे देश में एक विशिष्ट स्थान रखता है। यह उल्लेखनीय है कि त्रिपुरा, मिजोरम देश के सबसे उच्च साक्षरता वाले राज्यों में से हैं। चीन के बाद असम चाय का दूसरा सबसे बड़ा वाणिज्यिक उत्पादक क्षेत्र है। एशिया का पहला तेल का कुआं असम के डिगबोई में है।

वर्तमान में, अगर हम तस्वीर के उज्ज्वल पक्ष को देखें, तो *इंडियास्पेंड* रिसर्च के मुताबिक, मेघालय का 9.7% का प्रभावशाली संवृद्धि दर सबसे तेजी से विकास करते राज्य मध्यप्रदेश के 9.5% की संवृद्धि दर से भी अधिक है। अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में तेजी से आगे बढ़ा है। केवल एक बड़े राज्य, कर्नाटक (12.9 मिलियन) की तुलना में पूरे एनईआर में 12.8 मिलियन लोग ही गरीबी रेखा के नीचे हैं। इसके विपरीत दूसरी ओर, 2011-12 में त्रिपुरा ने शहरी क्षेत्रों में 25.2% बेरोजगारी दर रिपोर्ट किया है, नगालैंड 23.8% की बेरोजगारी दर के साथ इसके काफी निकट है। सभी 08 राज्यों के लिए औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा बढ़ गया है, जबकि कृषि और संबद्ध गतिविधियों का हिस्सा घट गया है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक है और यह राष्ट्रीय रूझान के अनुसार है। यहां गरीबी का फैलाव काफी असमान रूप से है: मणिपुर सबसे गरीब है तो सिक्किम सबसे अमीर। वास्तव में, औपनिवेशिक काल से पूर्वोत्तर क्षेत्र आर्थिक वृद्धि की अत्यधिक असमान दर का गवाह रहा है। अंग्रेज़ों के लिए, पूर्वोत्तर कोयले, प्राकृतिक तेल, वन और चाय जैसे कच्चे माल का भंडार था। इन संसाधनों की एक बड़े पैमाने पर निकासी की गयी थी, जिसे प्रसंस्करण के लिए देश के अन्य भागों में निर्यात किया गया था। इस क्षेत्र ने हालांकि इस प्रक्रिया से लाभ नहीं उठाया क्योंकि ब्रिटिश ने यहां न तो प्रसंस्करण और विनिर्माण इकाइयां स्थापित कीं और न ही उन्होंने इस क्षेत्र में परिवहन और संचार सुविधाओं के विकास की ओर कोई ध्यान दिया। भारत के विभाजन के बाद, लंबे समय तक, बांग्लादेश (पूर्वी पाकिस्तान) के साथ व्यापार रुका हुआ था जिसने इस क्षेत्र की आर्थिक और विकास क्षमता को काफी क्षति पहुंचाई। इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र और शेष भारत के बीच का अंतर भी बढ़ गया। हाल के दिनों में तस्वीर कुछ बेहतर हुई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र ने दोनों लिंगों के लिए मानव विकास संकेतकों के संबंध में अखिल भारतीय औसत स्थितियों की तुलना में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है लेकिन यह अनुरूप आर्थिक विकास लाने में विफल रहा है। आइए तनिक गहराई से देखें। जीएसडीपी, पीसीआई और संवृद्धि दर की क्षेत्रवार स्थिति तालिका 1 में प्रस्तुत है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र की धीमी प्रगति के पीछे निम्नलिखित कारण हैं: -

भौगोलिक कारक

पूर्वोत्तर क्षेत्र का तकरीबन 70% इलाका पहाड़ी है और इसमें लगभग 30% आबादी

लेखिका राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) हरियाणा, क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ में सहायक महाप्रबंधक हैं। उनकी 400 से अधिक रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं और वे आकाशवाणी व दूरदर्शन के वार्ता/पैनल परिचर्चा में भाग लेती रही हैं। ईमेल: manjula.jaipur@gmail.com

तालिका 1 : जीएसडीपी, पीसीआई और संवृद्धि दर की क्षेत्रवार स्थिति

क्र.	राज्य	आबादी 2011	जीएसडीपी (रु. करोड़ में)		प्रति व्यक्ति आय (एनएसडीपी) (रु.)		2011-12 के मूल्यों के आधार पर जीएसडीपी वृद्धि (2016-17ए)
			मौजूदा दर पर	स्थिर कीमत पर (2011-12)	मौजूदा दर पर	स्थिर कीमत पर (2011-12)	
1	आंध्र प्रदेश	84,580,777	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2	अरुणाचल प्रदेश	1383727	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3	असम	31205576	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4	बिहार	104099452	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5	छत्तीसगढ़	25545198	290140	223932	91772	71214	लागू नहीं
6	गोआ	1458545	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
7	गुजरात	60439692	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
8	हरियाणा	25351462	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
9	हिमाचल प्रदेश	6864602	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
10	जम्मू कश्मीर	12541302	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
11	झारखंड	32988134	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
12	कर्नाटक	61095297	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
13	केरल	33406061	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
14	मध्य प्रदेश	72626809	640484	465212	72599	51852	12.21
15	महाराष्ट्र	112374333	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
16	मणिपुर	2570390	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
17	मेघालय	2966889	29567	24005	79332	63678	6.65
18	मिज़ोरम	1097206	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
19	नागालैंड	1978502	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
20	ओडिशा	41974218	378991	314364	75223	61678	7.94
21	पंजाब	**27743338**	427870	348487	128821	103726	5.93
22	राजस्थान	68548437	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
23	सिक्किम	610577	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
24	तमिलनाडु	72147030	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	तेलंगना		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	त्रिपुरा	3673917	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	उत्तर प्रदेश	199812341	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	उत्तराखंड	10086292	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	पश्चिम बंगाल	91276115					
30	अंडमान निकोबार	380581	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
31	चंडीगढ़	1055450	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32	दिल्ली	16787941	622385	498217	303073	240318	8.26
33	पुड्डुच्चेरी	1247953	29557	23656	190384	150369	7.49
34	**संपूर्ण भारत**	**1210569573**	**15183709**	**12189854**	**103219**	**82269**	**7.1**

स्रोत: (1) आर्थिक एवं सांख्यिकीय संगठन, पंजाब (2) केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, नई दिल्ली

रहती है और शेष 30% इलाका समतल है जहां 70% आबादी निवास करती है। भौगोलिक कारणों व अविकसित परिवहन व्यवस्था की वज़ह से शेष भारत के साथ संपर्क हमेशा मुश्किल रहा है। साथ ही, असम के ब्रह्मपुत्र और बराक घाटियों में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित होने की वज़ह से न सिर्फ असम बल्कि अन्य राज्यों पर भी काफी दबाव पड़ता है।

ढांचागत कारक

पूर्वोत्तर राज्यों के आर्थिक पिछड़ेपन के कारणों में से एक है- सड़क मार्ग, जलमार्ग, ऊर्जा जैसे बुनियादी सुविधाओं आदि की बुरी स्थिति और शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे सामाजिक बुनियादी संरचना क्षेत्र के मानव विकास और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय सड़क का लगभग 6% और राष्ट्रीय राजमार्गों का लगभग 13% है। हालांकि, खराब रखरखाव के कारण इन सड़कों की स्थिति अच्छी नहीं है। इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे में कमी के प्रमुख संकेतक हैं: संकरी सड़कें, बिजली की खराब स्थिति, पेयजल की कमी आदि।

औद्योगिक विकास की दिशा में बाधाएं

आजादी के वक्त, असम एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र था, जहां ज्यादातर औपनिवेशिक पूंजीपतियों का वर्चस्व था। इस क्षेत्र में वृक्षारोपण और चाय का उत्पादन, कोयला और तेल के खनन, तेल रिफाइनरी, प्लाईवुड का निर्माण और अन्य वन संसाधन आधारित उत्पाद शामिल थे। आजादी के बाद भारत के विभाजन के कारण, असम के औद्योगिक क्षेत्र को एक गहरा झटका लगा क्योंकि उसके व्यापारिक मार्ग को देश के बाकी हिस्सों से काट दिया गया। इसकी वज़ह से भारत के अन्य हिस्सों के साथ आर्थिक एकीकरण में बाधा आई और निवेश के एक गंतव्य के रूप में इस क्षेत्र का आकर्षण कम हुआ। औद्योगिक विकास के लिए इस क्षेत्र की मुख्य शक्ति इसका विशाल प्राकृतिक संसाधन है। उदाहरण के लिए, क्षेत्र की विशाल जल विद्युत क्षमता के उपयोग हेतु नैशनल हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन और तेल एवं गैस रिज़र्व्स के संग्रहण व पर्यवेक्षण हेतु गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) व ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1995 में वृक्षों की कटाई को प्रतिबन्धित किए जाने की वज़ह से वन आधारित औद्योगिक इकाइयों में गिरावट आई है। इसके अलावा, स्थानीय पूंजी, विपणन और परिवहन बाधाओं की कमी से इस क्षेत्र का औद्योगिक विकास बाधित हुआ है। चाय उद्योग भारत के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अच्छी शुरुआत हुई, चाय उद्योग असम के एक प्रमुख विनिर्माण उद्योग के रूप में स्थापित हुआ। चाय उद्योग को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, उनमें से एक असम के वासियों और मजदूरों के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों और मजदूरों के कल्याणकारी लाभों के बीच की बहस है।

पूर्वोत्तर के विकास पर समग्र ध्यान देने के लिए, 1971 में भारत सरकार ने पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना की। सभी 8 राज्य इसके सदस्य हैं। इसका मुख्यालय शिलौंग में स्थित है। यह भारतीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत कार्य करता है। आरंभ में परिषद एक सलाहकार निकाय के रूप में स्थापित की गई, जिसे 2002 से एक क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में मंजूरी दे दी गई।

कृषि

कृषि यहां की जनजातीय आबादी की प्रमुख आजीविका होने के बावजूद कृषि विकास का पैटर्न राज्यों और फसलों के बीच असमान रहा है। चावल (खरीफ) इस क्षेत्र की प्रमुख फसल है। इस क्षेत्र में उगाए जाने वाले अन्य फसल (रबी) गेहूं, आलू, गन्ना, दाल और तिलहन हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र देश के कुल अनाज उत्पादन का केवल 1.5% उत्पादन करता है और 70% आबादी को आजीविका में मदद देता है। पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कृषि विकास की गति देश के बाकी हिस्सों से धीमी रही है। हरित क्रांति देश के उत्तर-पश्चिमी भागों तक सीमित रही और पूर्वोत्तर के क्षेत्रों को इसका लाभ नहीं मिला। इन क्षेत्रों में कृषि संबंधी उत्पादन की स्थिति परंपरागत है। कुछ क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता सबसे कम है, सिंचाई सुविधाएं लगभग गैर-मौजूद हैं और उर्वरकों की खपत काफी कम है। पूर्वोत्तर में सबसे प्रचलित कृषि पद्धतियों में से एक 'शिफ्टिंग' या 'झूम' खेती है। लगभग 1.7 मिलियन हेक्टेयर भूमि इसके अधीन है जो बड़े पैमाने पर वनों की कटाई का कारण बनता है जिसके परिणामस्वरूप मिट्टी का कटाव और मिट्टी की उर्वरता का नुकसान होता है।

प्राकृतिक संसाधन आधार

मिट्टी, पानी, वनस्पति और हाइड्रोकार्बन जैसे प्राकृतिक संसाधनों का खजाना होने के बावजूद देश का पूर्वोत्तर क्षेत्र अविकसित है क्योंकि संसाधनों का अंधाधुंध रूप से दोहन किया जा रहा है और दुरूपयोग किया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत ही संपत्ति नष्ट हो रही है जो आमतौर पर पूर्वोत्तर के क्षेत्रों के विकास और संवृद्धि के लिए सबसे बड़ी क्षमता को ट्रिगर करने हेतु रेखांकित की जाती है। इसके अलावा क्षेत्र की जैव विविधता भी खतरे में है। कोयला खनन, उर्वरक उद्योग, पेपर इंडस्ट्री, सीमेंट उद्योग और आतंकी गतिविधियों के कारण प्राकृतिक संसाधन प्रभावित हुए हैं।

परिवहन और संचार

पूर्वोत्तर क्षेत्र का परिदृश्य बिल्कुल भी प्रभावी नहीं है। विभिन्न भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक कारणों के कारण क्षेत्र में सड़क विकास बहुत धीमा रहा है। पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान, पूर्वोत्तर को परिवहन क्षेत्र के विकास के लिए आवंटित धनराशि इसकी आवश्यकता के मुकाबले पर्याप्त नहीं थी। अपर्याप्त परिवहन सुविधा एक गंभीर समस्या रही है जिसने लंबे समय तक इस क्षेत्र के विकास को बाधित किया है। विभाजन के परिणामस्वरूप, इस क्षेत्र ने उपभोक्ता वस्तुओं की अपेक्षाकृत ऊंची कीमतों और एक उच्च लागत वाली अर्थव्यवस्था के रूप में न केवल आर्थिक रूप से नुकसान सहा है बल्कि पूरे देश से अलगाव भी भोगा है। इसके अलावा, रेलवे नेटवर्क भारत के रेल नेटवर्क का केवल 4% है। न्यू बोंगाईगांव का पूरा नेटवर्क मीटर गेज़ में था और जो समस्याएं थीं उनमें न केवल अपर्याप्त रेलवे नेटवर्क बल्कि गेज के परिवर्तन के कारण हो रही बाधा शामिल थी। इस क्षेत्र ने आवश्यक वस्तुओं

मसलन सीमेंट, स्टील, खाद्यान्न, नमक आदि के परिवहन में गंभीर समस्याओं का सामना किया है।

आज के समय में पूर्वोत्तर क्षेत्र के समक्ष वैश्वीकरण भी एक बड़ी चुनौती है। भारत के 'एक्ट ईस्ट' नीति के साथ, जो भारत के पश्चिम उन्मुख रुख को पूर्व की ओर मोड़ रहा था, पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए व्यापार व कारोबार में विदेशी उद्योगों व एमएनसी के साथ सफलतापूर्वक प्रतियोगिता करना काफी कठिन है।

क्षेत्र का सामाजिक विघटन भी चिंता का मामला है। एक समाज जिसका उत्पादक बल अपर्याप्त है, वह अपने सदस्यों को कमज़ोर करता है और इस तरह का समाज सांस्कृतिक पूंजी के संबंध में निर्धन है और यदि ऐसे समाज का जीवन स्तर इसके उत्पादक बल के वहन किए जाने से अधिक है तो ऐसे समाज की आर्थिक स्थिति नैतिक अपकर्ष की स्थिति पैदा करती है।

शिक्षा प्रणाली यहां बुरी तरह विफल रही है। समृद्ध परिवार अपने बच्चों को आगे की शिक्षा के लिए कुछ खास शहरों में भेजते हैं जिससे स्थानीय समाज को एक बड़ा आर्थिक झटका लगता है। इस समस्या का समाधान किए जाने की ज़रूरत है।

नशे की आदत एक अन्य बड़ी समस्या है। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि इस क्षेत्र की 30% से अधिक आबादी नशीले ड्रग्स का उपयोग करते हैं। मणिपुर, नागालैंड, मिज़ोरम में तेजी से फैल रहा एचआईवी/एड्स गंभीर चिंता का विषय है।

पूर्वोत्तर के विकास पर समग्र ध्यान देने के लिए, 1971 में भारत सरकार ने पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना की। सभी 8 राज्य इसके सदस्य हैं। इसका मुख्यालय शिलौंग में स्थित है। यह भारतीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत कार्य करता है। आरंभ में परिषद एक सलाहकार निकाय के रूप में स्थापित की गई, जिसे 2002 से एक क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में मंजूरी दे दी गई। अब ये उन बातों पर चर्चा करते हैं जिनमें पूर्वोत्तर राज्यों का हित शामिल हो और ऐसे मामलों पर कार्रवाई करने का निर्णय लेते हैं। ऐसा पूर्वोत्तर राज्यों के आर्थिक और सामाजिक नियोजन का ख्याल रखने तथा अंतरराज्यीय विवादों की स्थिति में मध्यस्थता प्रदान करने के लिए किया गया।

पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड (एनईडीएफसीएल) एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के सूक्ष्म, लघु, मध्यम और बड़े उद्यमों को सहायता प्रदान करती है। एमडीओएनईआर के तहत अन्य संगठनों में पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड (एनईआरएएमएसी), सिक्किम माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (एसएमसी) और पूर्वोत्तर हथकरघा और हस्तशिल्प विकास निगम (एनईएचएचडीसी) शामिल हैं।

सितंबर 2001 में स्थापित पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के आठ राज्यों के सामाजिक-आर्थिक विकास से संबंधित मामलों के लिए केंद्र सरकार के नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है, बुनियादी ढांचागत बाधाओं को दूर करना, बुनियादी न्यूनतम सेवाओं का प्रावधान, निजी निवेश हेतु वातावरण बनाना और क्षेत्र में स्थायी शांति और सुरक्षा के लिए बाधाओं को दूर करने जैसे मामलों में राज्य सरकारों व केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के बीच सुविधाप्रदाता के रूप में काम करता है। क्षेत्र के एकीकृत विकास के लिए एजेंसी की भूमिका को प्राप्त करने के अपने प्रयास में, परिषद ने कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे बिजली, परिवहन, संचार और स्वास्थ्य को चिह्नित किया है।

एनईसी का बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से क्षेत्र के बिजली क्षेत्र में एक उल्लेखनीय योगदान है। जलविद्युत परियोजनाओं और गैस आधारित परियोजना

को जोड़ने के कारण इस क्षेत्र की उत्पादन क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। परिषद ने पावर ट्रांसमिशन सिस्टम को व्यवस्थित करने और नैशनल ग्रिड को क्षेत्र से जोड़ने की दिशा में भी पहल की है। इसके अलावा, एनईसी शुरुआत से, सड़कों और जलमार्गों के विकास में भी शामिल रहा है। एनईसी की स्थापना के समय, खेती का क्षेत्र लगभग 12 प्रतिशत था, जिसने इस क्षेत्र में कृषि वस्तुओं की मांग और आपूर्ति के बीच एक बड़ा अंतर तैयार किया। संशोधित किस्मों की उच्च गुणवत्ता वाले बीज की उपलब्धता, सिंचाई सुविधाओं की कमी, उर्वरक के आंदोलन में परिवहन की बाधाओं आदि की अनुपलब्धता आदि की वज़ह से उत्पादकता प्रभावित हुई है। इन बाधाओं पर काबू पाने के लिए, एनईसी ने अपने कृषि और संबद्ध क्षेत्र के माध्यम से कई कदम उठाए हैं।

इन वर्षों में एनईसी ने क्षेत्र के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में छात्रों के लिए सीटों के आरक्षण के माध्यम से सभी संघटक राज्यों के स्वास्थ्य श्रमशक्ति विकास की दिशा में काफी योगदान दिया है। एनईसी ने विभिन्न संसाधन जांच और सर्वेक्षणों के संचालन के माध्यम से पूर्वोत्तर के क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों के विकास के लिए योग दिया है। इसने संसाधन उपलब्धता और दस्तावेज़ीकरण के बारे में ज्ञान आधार बनाने में मदद की है। पूर्वोत्तर के औद्योगिक विकास के लिए एनईसी का प्रयास उद्यमियों की पहली पीढ़ी को विकसित करने में भी रहा है। इसके परिणामस्वरूप क्षेत्र में विभिन्न छोटी इकाइयां स्थापित हुई है। फॉरवर्ड लिंकेज विकसित करने के लिए, एनईसी ने एनईआरएएमसी जैसे विपणन एजेंसियों की स्थापना के द्वारा योगदान दिया है, प्रदर्शनियों, सेमिनारों और व्यवसाय बैठकों के आयोजन में सहायता दी है। काउंसिल ने पालन-पोषण अन्य हथकरघा उत्पादों के लिए सुविधाएं प्रदान करके रेशम उत्पादन के विकास में योग दिया है। एनईसी ने सिक्किम समेत पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास परिदृश्य बिल्कुल भी प्रभावी नहीं है। विभिन्न भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक कारणों के कारण क्षेत्र में सड़क विकास बहुत धीमा रहा है। पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान, पूर्वोत्तर को परिवहन क्षेत्र के विकास के लिए आवंटित धनराशि इसकी आवश्यकता के मुकाबले पर्याप्त नहीं थी। अपर्याप्त परिवहन सुविधा एक गंभीर समस्या रही है जिसने लंबे समय तक इस क्षेत्र के विकास को बाधित किया है।

इसने पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय क्षरण के समाधान की दिशा में भी कदम उठाए हैं। इसने 3400 हेक्टेयर में फैले 1700 झुमिया परिवारों को परंपरागत खेती पद्धतियों से दूर करने में सहयोग दिया है। कृषि क्षेत्र में किए गए कुछ प्रयास जलस्तर विकास, खेती और व्यापार के वैकल्पिक तरीकों से संबंधित प्रशिक्षण हैं।

हाल ही में दिसंबर, 2017 में वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए विकास संबंधी पहलों के संबंध में, केंद्र ने पूर्वोत्तर विशेष बुनियादी ढांचा विकास योजना को अनुमोदन दिया है जो दो क्षेत्रों- एक, जल आपूर्ति, विद्युत, कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं से संबंधित भौतिक आधारभूत संरचना है, दूसरी, शिक्षा व स्वास्थ्य संबंधी सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाएं हैं- में बुनियादी ढांचे के निर्माण में अंतराल को भर देगा। इस योजना की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि यह एनएलसीपीआर, जहां 10% योगदान राज्य सरकार से आना था, के मुकाबले 100% केंद्रीय रूप से वित्त पोषित योजना है। भारत सरकार इस योजना के तहत अगले तीन वर्षों में पूर्वोत्तर राज्यों को 5300 करोड़ रूपये प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त, ट्यूरिअल हाइड्रो-पावर प्रोजेक्ट मिजोरम में सफलतापूर्वक आरंभ किया जाने वाला पहला प्रमुख केंद्रीय परियोजना है। यह प्रति वर्ष 251 मिलियन विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करेगा और राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। इसी के साथ, सिक्किम और त्रिपुरा के बाद एनआईआर में मिजोरम तीसरा विद्युत अधिशेष राज्य बन गया है। तथ्य यह है कि वित्तीय बाधाओं के बावजूद पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं का शेयरिंग पैटर्न 90-10 बना हुआ है, जो खुद पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर वर्तमान सरकार की चिंता को दर्शाता है। इसके अलावा पिछले तीन वर्षों के दौरान 32,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग के 3800 किमी को मंजूरी दी गई है जिनमें से लगभग 1200 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जा चुका है।

कृषि यहां की जनजातीय आबादी की प्रमुख आजीविका होने के बावजूद कृषि विकास का पैटर्न राज्यों और फसलों के बीच असमान रहा है। चावल (खरीफ) इस क्षेत्र की प्रमुख फसल है। इस क्षेत्र में उगाए जाने वाले अन्य फसल (रबी) गेहूं, आलू, गन्ना, दाल और तिलहन हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र देश के कुल अनाज उत्पादन का केवल 1.5% उत्पादन करता है और 70% आबादी को आजीविका में मदद देता है।

रेल नक्शे पर पूर्वोत्तर के सभी राज्य की राजधानियों को लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार पूर्वोत्तर में विशेष गतिशील सड़क विकास कार्यक्रम के तहत 60,000 करोड़ और क्षेत्र में उच्च-मार्गों और सड़कों के नेटवर्क बनाने हेतु अगले 2 से 3 वर्षों में भारतमाला के तहत 30,000 करोड़ का अतिरिक्त निवेश करेगी। 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' को सक्रियता से अपनाते हुए किए गए कुछ प्रमुख पहलों में कलदन मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, आरआईएच-टेदीम रोड प्रोजेक्ट और बॉर्डर हाट्स शामिल हैं। केंद्र सरकार ने पर्यावरण पर्यटन और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पिछले दो वर्षों में मिजोरम के लिए रु. 194 करोड़ की दो पर्यटन परियोजनाओं को मंजूरी दी है जिनमें इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए रु. 115 करोड़ रुपये पहले ही संवितरित किए जा चुके हैं।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बांस पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाखों लोगों की आजीविका का साधन है, भारत सरकार ने हाल ही में अपने प्रतिबंधात्मक विनियामक शासन को हटा दिया है। अब बांस उत्पादों के उत्पादन, परिवहन और बिक्री के लिए किसी भी परमिट की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इससे लाखों किसानों को फायदा होगा और 2022 तक 'किसानों की आय को दुगुना करने के प्रयासों में मदद मिलेगी।

यदि हम नवीनतम बजट (2018-19) को देखें, तो सरकार ने 50 हवाई अड्डों के पुनरुद्धार और विमानन अवसंरचना में सुधार के लिए रु. 1014.09 करोड़ (पिछले वर्षों आबंटित राशि का 5 गुना) आवंटित किया है। इनमें सिक्किम में पाकींग, अरुणाचल प्रदेश में तेजू हवाई अड्डे आदि जैसे शामिल हैं, जहां पहली बार नागरिक हवाई संपर्क प्रदान किया जाएगा।

उम्मीद है कि इन सभी प्रयासों से आर्थिक लिंकेज की संभवानाओं का विस्तार होगा और इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र की समग्र आर्थिक संवृद्धि व विकास में मदद मिलेगी। क्षेत्र की उच्च साक्षरता दर, प्राकृतिक सुंदरता और अंग्रेजी बोलने वाली बड़ी आबादी राज्य को आदर्श पर्यटक स्थल के रूप में स्थापित करती है।

भावी रूपरेखा

क्षेत्र के व्यापक विकास के लिए एक छह चरणीय रणनीति प्रस्तावित की गई है:

- समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए ज़मीनी स्तर वाली योजना के माध्यम से स्व-शासन और भागीदारी विकास को अधिकतम करते हुए लोगों को सशक्त बनाना।
- ग्रामीण कृषीतर रोज़गार के ज़रिए पशुपालन, बागवानी, फूलों की खेती, मत्स्य पालन जैसी कृषि व संबद्ध गतिविधियों में उत्पादकता बढ़ाने व आजीविका विकल्पों के सृजन के ज़रिए ग्रामीण क्षेत्रों में विकास संभावनाओं का सृजन।
- तुलनात्मक लाभ वाले क्षेत्र में कृषि-प्रसंस्करण, जल विद्युत उत्पादन जैसे क्षेत्रों का विकास करना।
- सरकार व बाहर की संस्थाओं के लिए क्षमता का निर्माण व लोगों के कौशल व दक्षताओं का संवर्द्धन।
- आधारभूत संरचना के लिए खास तौर पर निजी क्षेत्र द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक उपयुक्त निवेश वातावरण बनाना।
- इन उद्देश्यों को साकार करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के संसाधनों का उपयोग करना।

03 फरवरी 2018 को गुवाहाटी में संपन्न ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मिट का नवीनतम कार्यक्रम स्वयं पूर्वोत्तर क्षेत्र में समग्र समृद्धि लाने की दिशा में एनडीए सरकार के ईमानदार दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। कार्यक्रम ने निस्सन्देह विनिर्माण, सेवाएं, विद्युत, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, आईटी, परिवहन, पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल और हस्तशिल्प और पर्यटन सहित क्षेत्रों में दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में राज्यों की निवेश संभावना को प्रदर्शित किया।

निष्कर्षत: नवाचार, पहल, विचार और कार्यान्वयन, इन चारों को एक साथ काम करने की जरूरत है। बेहतर प्रशासन पर ज़ोर देते हुए समावेशी विकास के माध्यम से समावेशी संवृद्धि लाने और मूलभूत आवश्यकताओं व सेवाओं के कार्यान्वयन हेतु स्थानीय समुदायों के समर्थित होने को सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। इसके लिए, सभी हितधारकों को पूर्वोत्तर के राज्यों के समग्र विकास के लिए एक सर्व-व्यापी यथार्थवादी योजना तैयार करने की आवश्यकता है। ❑

मणिपुर में 105वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस

प्रधानमंत्री ने मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल में 105वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए वैज्ञानिकों को मानवहित के लिए अपने शोध को "प्रयोगशाला से जीवन" तक विस्तारित करने के लिए प्रेरित किया और कहा कि "शोध एवं विकास" को देश के विकास हेतु अनुसंधान के रूप में पुनर्परिभाषित किए जाने की ज़रूरत है।

उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व समय की मांग है। विज्ञान व प्रौद्योगिकी में अनुसंधान व विकास का अभिप्राय राष्ट्रीय विकास के लिए इसके उपयोग व जनता के कल्याण के लिए सेवारत होने से है। उन्होंने विश्व भर के वैज्ञानिक समुदाय से विज्ञान व प्रौद्योगिकी की बड़ी समस्याओं के प्रभावी समाधान हेतु सहयोग की अपील की। ❑

मणिपुर में एक प्रदर्शनी के दौरान बच्चों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी